



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]
No. 166]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 1, 1982/वैसाख 11, 1904
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 1, 1982/VAISAKHA 11, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मई, 1982

का० आ० 295(अ) —“दल खालसा” के नाम से जात संगठन—

(i) जिसने एक संपूर्ण स्थायील “खालसा राज्य” स्थापित करना अपना मुख्य उद्देश्य घोषित किया था, अपने उद्देश्य के अनुसरण में भारत के एक भाग को विलग करने और अपने उत्तराधियों के साथ से संघ का राज्यशेषीय अधिकारों को विवरण करने का प्रचार करता रहा है।

(ii) उपरीक उद्देश्य के अनुसरण में 29 नवम्बर, 1981 को इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण करके लाहौर ले जाने के लिए और अन्य बासों के साथ साथ, भारत मरकार द्वारा एक अलग सिव राज्य जिसे “खालिस्तान” कहा जाएगा, को स्वीकार किए जाने की मांग करने के लिए “दल खालसा” के पांच सदस्यों को नियंत्रित किया था।

(iii) 26 अप्रैल, 1982 को अमृतसर में हुई प्रधिकारी घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए जब गायों के कटे हुए शेर मिश्न मंदिरों के पास रखे पाए गए थे और ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति की प्रक्रिया देकर विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच लोक व्यवस्था और सेन-मिलाप बनाए रखने के प्रतिकूल श्रियाकल्प जारी रखने का अपना आशय स्पष्ट कर दिया था।

और केन्द्रीय मरकार की राय है कि पूर्वोक्त कारणों के “दल खालसा” एक विधिविरुद्ध समूह है,

प्रोर केन्द्रीय मरकार की यह भी राय है कि भानक और हिमा के कार्यों और “दल खालसा” के मदद्यों द्वारा द्वारा द्वारा ही में किए गए प्रधिकारी कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करने के कारण “दल खालसा” को सुरक्षा विधिविरुद्ध धार्यांशक करना आवश्यक है;

अन. केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध श्रियाकल्प (निवारण) प्रधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त गतिकों का प्रयोग करने हुए “दल खालसा” को एक विधि-विरुद्ध संगम घोषित करती है और उस धारा की उपधारा (3) के परन्तु द्वारा प्रदत्त गतियों का प्रयोग करने हुए, निवेश देती है कि यह प्रधिकूचना उम्मा भारत के, जो उन प्रधिनियम की धारा 4 के अधीन विधि जा सकता है, मधीन रहते हुए, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[का० मं० 4/19/81-टी]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 1st May, 1982

S.O. 295(E).—Whereas the organisation known as ‘Dal Khalsa’—

- (i) which had declared as its main objective the establishment of a complete autonomous ‘Khalsa State’ has, in pursuance of its objective, been preaching secession and disruption of the territorial integrity of India through its activities;
- (ii) had in furtherance of the aforesaid objective, employed five of the members of the ‘Dal Khalsa’ to hijack an aircraft of the Indian Airlines to

Lahore on 29th September, 1981 and to demand inter-alia the acceptance by the Government of India, of the establishment of a separate Sikh State to be called, Khalistan;

- (iii) has by owning up responsibility for the incidents which took place in Amritsar on the 26th April, 1982 when two severed heads of cows were found placed near Hindu temples, followed by its threat to repeat such incidents in future, made clear its intention to continue to resort to activities prejudicial to the maintenance of public order and harmony between different religious groups;

And whereas, the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the 'Dal Khalsa' is an unlawful association;

And whereas, the Central Government is further of the opinion that because of the acts of terrorism and violence and the recent acts of sacrifice owned by members of 'Dal Khalsa' it is necessary to declare the 'Dal Khalsa' to be unlawful with immediate effect;

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the 'Dal Khalsa' to be an unlawful association, and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 4/19/81-T]

**का० आ० 296(अ) —‘नेशनल काउन्सिल ब्राह्मणिस्तान’
(जिसे हमें हमके पश्चात् काउन्सिल कहा गया है) के नाम से ज्ञात संगठन—**

(i) जिसने हमके महासचिव, बलबीर सिंह मंथु के माध्यम से एक स्थायी, अलग सिख राज्य “ब्राह्मणिस्तान” की स्थापना करना प्रयत्न उद्देश्यित किया था, “दल ब्राह्मण” नाम से ज्ञात संगठन के विलगकारी और हिम्मातमुक्त क्रियाकलापों का प्रोत्साहन करता रहा है;

(ii) पूर्वोक्त उद्देश्य को प्रगति करने के लिए—

(क) तथाकथित “ब्राह्मणिस्तान” गणराज्य के पांच डालर के करेंसी नोट;

(ख) ब्राह्मणिस्तान के डाक महसूल स्टाम्प और

(ग) तथाकथित ब्राह्मणिस्तान भरकार के पासपोर्ट जारी करने के विलगकारी क्रियाकलाप में लगा दुआ था।

और केंद्रीय सरकार की गय है कि पूर्वोक्त कारणों से काउन्सिल एक विश्विष्ट संगठन है।

और केंद्रीय सरकार की यह भी गय है कि इनसे उद्देश्य को प्रगति करने के लिए कानून बनाया गया, इस ब्राह्मणिस्तान को प्रोत्साहन देने के कारण काउन्सिल को तुरन्त विश्विष्ट घोषित करना आवश्यक है;

अब केंद्रीय सरकार विश्विष्ट क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 17) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त विषयों का पर्याप्त करने के लिए काउन्सिल ब्राह्मणिस्तान को विश्विष्ट संगठन घोषित करती है और उन ब्राह्मणिस्तान की उपधारा (3) के परन्तु द्वारा प्रदत्त विषयों का प्रयोग करते हुए, निश्चियता है कि यह अधिनियम उम्मीद के, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के प्रधीन दिया जा रहा है अवीन रुप्रे द्वारा, राजपत्र में प्रकाशन की जारी होगी।

[फा० ४/१९/८१-टी]
ज्ञा० एस० ग्रेवाल, संयुक्त सचिव

S.O. 296(E).—Whether the organisation known as ‘the National Council of Khalistan’ (hereinafter referred to as the Council) :—

- (i) which had through the declaration of Shri Balbir Singh Sandhu, its Secretary General, proclaimed as its objective the establishment of an autonomous, separate Sikh State of ‘Khalistan’ has been encouraging the secessionist and violent activities of the organisation known as ‘Dal Khalsa’ ;
- (ii) had, in furtherance of the aforesaid objective, indulged in secessionist activity by issuing—
- (a) five dollar currency Notes of the so-called Republic of ‘Khalistan’ ;
 - (b) postage stamps of ‘Khalistan’ ; and
 - (c) pass-portes of the so-called Government of ‘Khalistan’ ;

And whereas, the Central Government is of opinion that for the reasons aforesaid, the Council is an unlawful association ;

And whereas, the Central Government is further of the opinion that because of the encouragement being given to the ‘Dal Khalsa’ by the Council for the furtherance of its objective it is necessary to declare the Council to be unlawful with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares ‘the National Council of Khalistan’ to be an unlawful association and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 4/19/81-T]
G. S. GREWAL, Jt. Secy.